

रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML-2008.



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 8 अप्रैल, 2008/19 चैत्र, 1930

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-171004, 4 अप्रैल, 2008

संख्या वि० स०-विधायन-अधिक मांगें/1-42/2008.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक-4) विधेयक, 2008 (2008 का विधेयक संख्यांक-7) जो आज दिनांक 4 अप्रैल, 2008 को

हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

हस्ताक्षरित /—

सचिव,
हिमाचल प्रदेश विधान सभा ।

2008 का विधेयक संख्यांक 7**हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2008**

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से, वित्तीय वर्ष 2002-03 में, कतिपय सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिए प्राधिकृत या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए, कतिपय रकम के विनियोजन को प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने के लिए **विधेयक ।**

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 2008 है । संक्षिप्त नाम ।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट राशियां, जिनका योग 32,95,75,77,342 (बत्तीस अरब, पच्चावने करोड़ पच्चहत्तर लाख सतहत्तर हजार तीन सौ बियालीस रुपये केवल) है, वित्तीय वर्ष 2002-2003 के दौरान अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवाओं से सम्बन्धित प्रभारों को चुकाने के लिए, उन सेवाओं और उस वर्ष के लिए प्राधिकृत या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए संदत्त किए जाने और उपयोजन के लिए प्राधिकृत समझी जाएंगी । हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिए कतिपय व्ययों को पूरा करने के लिए 32,95,75,77,342 रुपये की और राशि प्राधिकृत करना ।

3. इस अधिनियम के अधीन, हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से संदत्त और उपयोजन के लिए प्राधिकृत समझी जाने वाली राशियां, वित्तीय वर्ष 2002-2003 से सम्बन्धित अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित समझी जाएंगी । विनियोग ।

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखें)

1 मांग संख्या	2 सेवाएं और प्रयोजन	3 निम्नलिखित राशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा दत्तमत रुपये	संचित निधि पर प्रभारित रुपये	जोड़ रुपये
3	न्याय प्रशासन और निर्वाचन (राजस्व)	—	5,42,459	5,42,459
5	भू-राजस्व और जिला प्रशासन (राजस्व)	2,44,39,530	—	2,44,39,530
6	आबकारी और कराधान (राजस्व)	53,29,561	—	53,29,561
7	पुलिस और सम्बद्ध संगठन (राजस्व)	9,35,70,390	—	9,35,70,390
	(पूंजी)	50,00,000	—	50,00,000
9	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (राजस्व)	1,75,93,209	1	1,75,93,210
10	लोक निर्माण-भवन (राजस्व)	65,20,26,020	—	65,20,26,020
12	उद्यान (पूंजी)	75,84,896	—	75,84,896
13	सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण (राजस्व)	29,75,51,103	—	29,75,51,103
15	योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना (पूंजी)	5,97,79,890	—	5,97,79,890
17	सड़कें व पुल (राजस्व)	50,93,73,201	—	50,93,73,201
18	आपूर्ति, उद्योग और खनिज (पूंजी)	5,497	—	5,497
20	ग्रामीण विकास (राजस्व)	46,887	—	46,887

1	2	3		
		रुपये	रुपये	रुपये
23	जल और विद्युत विकास (राजस्व)	4,72,49,433	—	4,72,49,433
	(पूंजी)	1,04,41,46,000	—	1,04,41,46,000
27	श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण (राजस्व)	91,65,232	—	91,65,232
28	जलापूर्ति, सफाई, आवास (राजस्व)	90,56,55,191	—	90,56,55,191
	और नगर विकास (पूंजी)	49,52,387	—	49,52,387
29	वित्त (पूंजी)	—	29,11,03,61,016	29,11,03,61,016
31	जन जातीय विकास (राजस्व)	13,88,57,441	—	13,88,57,441
	(पूंजी)	2,43,47,998	—	2,43,47,998
	जोड़ (राजस्व)	2,70,08,57,198	5,42,460	2,70,13,99,658
	(पूंजी)	1,14,58,16,668	29,11,03,61,016	30,25,61,77,684
	कुल जोड़	3,84,66,73,866	29,11,09,03,476	32,95,75,77,342

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक, भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के खण्ड (1) के साथ पठित, अनुच्छेद 204 के खण्ड (1) के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2002–2003 के दौरान अनुदान और विनियोग से अधिक किए गए व्यय को पूरा करने के लिए और अधिक धन के विनियोजन का उपबन्ध करने के लिए पुरःस्थापित है ।

प्रेम कुमार धूमल,
मुख्य मन्त्री ।

शिमला :
तारीख 4 अप्रैल, 2008.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

[वित्त विभाग फाईल संख्या फिन. ए.-डी (4)-3 / 2007]

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2008 की विषय-वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन उक्त विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं ।

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2008

हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से, वित्तीय वर्ष 2002–2003 में कतिपय सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिए प्राधिकृत या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए, कतिपय रकम के विनियोजन को प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने के लिए **विधेयक**।

प्रेम कुमार धूमल,
मुख्य मन्त्री ।

जे० एन० बारोवालिया
प्रधान सचिव (विधि) ।

शिमला :

तारीख 4 अप्रैल, 2008.

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 7 of 2008.

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (No. 4) BILL, 2008

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to provide for the authorisation of appropriation of certain amount out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh to meet the amount spent on certain services for the financial year 2002-2003 in excess of the amount authorized or granted for those services for that year.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-ninth Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation (No. 4) Act, 2008.

Authorisation of a further sum of Rs. 32,95,75,77,342 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh to meet certain expenditure for the financial year 2002-2003.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, the sums specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of Rs. 32,95,75,77,342 (Thirty Two hundred Ninety Five crore, Seventy five lakhs, Seventy Seven thousand Three hundred Fourty Two rupees only) shall be deemed to have been authorized to be paid and applied to meet the amount spent for defraying the charges in respect of the services specified in column (2) of the Schedule during the financial year 2002-2003 in excess of the amount authorised or granted for those services for that year.

Appropriation.

3. The sums deemed to have been authorized to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh under this Act shall be deemed to have been appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the financial year 2002-2003.

THE SCHEDULE

(See sections 2 and 3)

1 No. of De- mand	2 Services and purposes		3		
			Sums not exceeding		
			Voted by the Legislative Assembly Rs.	Charged on the Consolidated Fund Rs.	Total Rs.
3	Administration of Justice (Revenue) And Election		—	5,42,459	5,42,459
5	Land Revenue and (Revenue) District Administration		2,44,39,530	—	2,44,39,530
6	Excise and Taxation (Revenue)		53,29,561	—	53,29,561
7	Police and Allied (Revenue) Organisations (Capital)		9,35,70,390 50,00,000	— —	9,35,70,390 50,00,000
9	Health and Family (Revenue) Welfare		1,75,93,209	1	1,75,93,210
10	Public Works— (Revenue) Buildings		65,20,26,020	—	65,20,26,020
12	Horticulture (Capital)		75,84,896	—	75,84,896
13	Irrigation and Flood (Revenue) Control		29,75,51,103	—	29,75,51,103
15	Planning and Backward (Capital) Area Sub-Plan		5,97,79,890	—	5,97,79,890
17	Roads and Bridges (Revenue)		50,93,73,201	—	50,93,73,201
18	Supplies, Industries and (Capital) Minerals		5,497	—	5,497

1	2	3		
		Rs.	Rs.	Rs.
20	Rural Development (Revenue)	46,887	—	46,887
23	Water and Power Development (Revenue)	4,72,49,433	—	4,72,49,433
	(Capital)	1,04,41,46,000	—	1,04,41,46,000
27	Labour, Employment and Training (Revenue)	91,65,232	—	91,65,232
28	Water Supply, Sanitation, Housing and Urban Development (Revenue)	90,56,55,191	—	90,56,55,191
	(Capital)	49,52,387	—	49,52,387
29	Finance (Capital)	—	29,11,03,61,016	29,11,03,61,016
31	Tribal Development (Revenue)	13,88,57,441	—	13,88,57,441
	(Capital)	2,43,47,998	—	2,43,47,998
	Total (Revenue)	2,70,08,57,198	5,42,460	2,70,13,99,658
	(Capital)	1,14,58,16,668	29,11,03,61,016	30,25,61,77,684
	Grand Total	3,84,66,73,866	29,11,09,03,476	32,95,75,77,342

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This Bill is introduced in pursuance of clause (1) of Article 204 read with clause (1) of Article 205 of the Constitution of India to provide for the appropriation from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh of the moneys further required to meet the expenditure on account of expenses in excess of grants and appropriations for the financial year 2002-2003.

PREM KUMAR DHUMAL,
Chief Minister.

SHIMLA :
The 4th April, 2008.

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[Finance Department File No. Fin. A-D (4)-3/2007]

The Governor, Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Appropriation (No. 4) Bill, 2008, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the aforesaid Bill in the Legislative Assembly.

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (No. 4) BILL, 2008

A

BILL

to provide for the authorisation of appropriation of certain amount out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh to meet the amount spent on certain services for the financial year 2002-2003 in excess of the amount authorized or granted for those services for that year.

PREM KUMAR DHUMAL,
Chief Minister.

J. N. BAROWALIA,
Principal Secretary (Law).

SHIMLA :
The 4th April, 2008.